

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयांकी,  
प्रभारी सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 17 फरवरी, 2016

**विषय:-** जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-थराली में अंगतोली-मजेठा-कोठा से सिलोड़ी हाईस्कूल मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र-थराली में अंगतोली-मजेठा-कोठा से सिलोड़ी हाईस्कूल मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं०:- 127/लो०नि०-1/2004-09(प्रा०आ०)/2004टी०सी० दि०: 16-2-2004 (क्रमांक-216) के द्वारा लम्बाई 6.00 किमी० तथा लागत ₹ 86.40 लाख की प्रदान की गई है। इस मोटर मार्ग की वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने तथा चैनेज 1.700 पर ग्राम चिड़िगां एवं कोठा में आपसी विवाद होने के कारण निर्माण कार्य बाधित रहा तथा वर्ष 2013 में विवाद सुलझने एवं इस मध्य श्रमिक एवं सामग्री की दरों अत्यधिक वृद्धि के दृष्टिगत विषयगत कार्य हेतु पूर्व स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण न होने के फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, पौड़ी द्वारा विभागीय तकनीकी परीक्षणोंपरान्त वर्तमान में शासन को उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित विस्तृत आगणन, जिसकी औचित्यपूर्ण पाई गई सम्पूर्ण पुनरीक्षित लागत ₹ 308.06 लाख (₹ 86.40 लाख पूर्व स्वीकृत लागत + ₹ 221.66 अतिरिक्त लागत) की प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की, माननीय श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश सं०:- 127/लो०नि०-1/2004-09(प्रा०आ०)/2004टी०सी० दि०: 16-2-2004 (क्रमांक-216) के द्वारा स्वीकृत लागत ₹ 86.40 लाख को, प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन पर विभागीय टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई पुनरीक्षित लागत ₹ 308.06 लाख से घटाते हुए, अतिरिक्त लागत ₹ 221.66 लाख में अवशेष कार्यों को पूर्ण करा लिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि, आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई हो अथवा अवशेष हो तो उस धनराशि को स्वीकृत लागत से समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यों पर अवमुक्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी। उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 16-02-2004 को केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

3- पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

5- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

6- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

8- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।



9- स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।

10- पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

11- उक्त योजना पर होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०:-22 लेखाधीनक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-01 चालू निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य की मद से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से किया जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा विभिन्न पत्रावलियों में दिये गये परामर्शानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( अरविन्द सिंह हयांकी )  
प्रभारी सचिव

संख्या:- 883 (1)/111(2)/15-09(प्रा०आ०)/2004टी०सी० तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी चमोली।
4. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/चमोली।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, गोपेश्वर/थराली।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( ए०एस०पांगती )  
उप सचिव